दैनिक जागरण
असफलताएं उपलब्धि की राह पर मील के पत्थर हैं

# यूरोपीय सांसदों का दौरा

यह समय ही बताएगा कि कश्मीर पहुंचे यूरोपीय संघ के सांसदों का नजरिया भारत के इस हिस्से के बारे में विश्व समुदाय के रुख-रवैये को प्रभावित करने में कितना सहायक होगा, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि यह घाटी के हालात पर भी निर्भर करेगा। यूरोपीय देशों के सांसदों के श्रीनगर पहुंचते ही आतंकियों ने जिस तरह पश्चिम बंगाल के मजदूरों को निशाना बनाया उससे यह स्पष्ट है कि कश्मीर के हालात ठीक करने में अभी समय लगेगा। निःसंदेह इसमें सफलता तब मिलेगी जब आतंकियों को छिपने-भागने के लिए विवश किया जाएगा। यदि आम कश्मीरी जनता कश्मीर को बदनाम करने और वहां दहशत फैलाने में जुटे आतंकियों के खिलाफ मुखर हो सके तो माहौल कहीं आसानी से बदला जा सकता है। हालांकि कश्मीर में पहले भी बाहरी लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में घाटी के बाहर के लोगों को जिस तरह चुन-चुनकर मारा गया उससे न केवल यह स्पष्ट है कि पाकिस्तानपरस्त आतंकी गैर कश्मीरियों में खौफ पैदा करने पर आमादा हैं, बल्कि यह भी कि उनकी तथाकथित लड़ाई का राजनीतिक अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं। सच तो यही है कि कश्मीर में अधिकारों के नाम पर आतंक का कारोबार जारी है और इसीलिए उन निर्दोष-निहत्थे लोगों को भी मारा जा रहा जो कश्मीर की भलाई के लिए वहां मेहनत-मजदूरी कर रहे हैं।

यूरोपीय देशों के सांसदों के साथ विश्व समुदाय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि कश्मीर गए ट्रक ड्राइवरों और वहां प्रवास कर रहे मजदूरों पर किए गए आतंकी हमलों में एक दर्जन लोगों को जान गंवानी पड़ी है। चूंकि ये आतंकी हमले पाकिस्तान के इशारे पर ही हो रहे हैं इसलिए इससे एक सीमा तक ही संतुष्ट हुआ जा सकता है कि यूरोपीय देशों के सांसदों ने कश्मीर में आतंक के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की हामी भरी। आखिर पाकिस्तान को जवाबदेह कब बनाया जाएगा? इससे भी जरूरी सवाल यह है कि उसे आतंकवाद को खाद-पानी देने के लिए दंडित कब किया जाएगा? इन सवालों के बीच यह अच्छा नहीं हुआ कि यूरोपीय देशों के सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। इससे बचा जाना चाहिए था। इन सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर उठाए गए विपक्ष के सभी सवालों को निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मांग में वजन है कि आखिर इन सांसदों को कश्मीर आमंत्रित करने के पहले विपक्षी नेताओं को वहां क्यों नहीं भेजा गया? इस जायज सवाल के बावजूद यह भी सही है कि विपक्षी नेताओं के कश्मीर दौरे को विश्व समुदाय में कोई अहमियत मिलने वाली नहीं थी।

# भागीदारी से बचेगी सांस

पटाखे कम फूटने के बाद भी बिहार में पटना की हवा मानक से 11 गुना ज्यादा जहरीली रही। कम आतिशबाजी के बाद भी दिवाली की आधी रात के बाद राजधानी की वायु गुणवत्ता में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 697 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक बढ़ गया, जो सामान्यतः 60 होना चाहिए। वैसे यह मात्रा 2018 की दिवाली से कम है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। हमें हर कीमत पर प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। इस बात का इंतजार छोड़ना होगा कि सरकार कुछ नियमन कर रोक लगाएगी। अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है कि पटाखे पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती है? ग्रीन पटाखा क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? ग्रीन पटाखा व्यावहारिक तौर पर इतना कीमती होगा कि उसे बाजार में सर्वसुलभ करना आसान नहीं है। कानून के माध्यम से पटाखे पर रोक न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है। कानून जरूर लागू हों, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों की काउंसिलिंग की जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। बच्चों के पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को समर्पित किया जाए। केवल दिवाली के समय प्रदूषण की चिंता न की जाए। साल भर स्कूल-कॉलेज और समाज में इस पर चर्चा हो, तभी कोई सार्थक नतीजा सामने आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, दोनों ही बिजली से चार्ज होने वाली कार का इस्तेमाल करने लगे हैं। सरकार का यह निर्णय भी है कि अधिक से अधिक सीएनजी के केंद्र खोले जाएं और डीजल-पेट्रोल वाले वाहनों की संख्या कम की जाए। इसका असर दिखने भी लगा है। बिहार के छोटे शहरों में भी ई-रिक्शा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। प्रदूषण की हालत यह है कि डॉक्टर सुबह की सैर तक न करने की सलाह दे रहे हैं। इस हालत को समझना होगा। जहरीली हवा बच्चे और उम्रदराज लोगों के लिए और भी जानलेवा है। पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-2.5 और इससे छोटे कण फेफड़े के जरिये रक्त में पहुंच जाते हैं। इस वजह से धमनियों में ब्लॉकेज की आशंका रहती है। अच्छी बात है कि पटना में कुछ नई जगहों पर भी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि लोग और भी जागरूक होकर प्रदूषण की वास्तविक चिंता करें।

> बच्चों के पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को समर्पित किया जाए। केवल दिवाली के समय प्रदूषण की चिंता न की जाए

# नई चुनौतियों से जूझती भाजपा



प्रदीप सिंह

**भाजपा के राजनीतिक विस्तार के रास्ते की बाधा केवल सामाजिक संतुलन को साधने और उसे मजबूत बनाने की ही नहीं है, कुछ सहयोगी भी हैं**




अवधेश राजपूत

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों ने क्या मोदी के अपराजेय होने के मिथक को तोड़ दिया है? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे इसी रूप में देखता है। लेफ्ट लिबरल बिरादरी ऐसा फतवा जारी करने की बहुत जल्दी में है। ऐसे विश्लेषकों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिलना और हरियाणा में भाजपा का एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनना, लेकिन बहुमत से कुछ दूर रह जाना, मोदी की हार है। हार-जीत के खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता भी है। यदि मोदी हार गए तो जीता कौन? 54 सीटें पाने वाले शरद पवार या 31 सीटें पाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा? जाहिर है कि तथ्यों से मतलब नहीं। बस कह दिया कि मोदी की हार हो गई या मोदी को हराया जा सकता है तो बात खत्म।

किसी भी घटना का विश्लेषण संदर्भ से काटकर नहीं किया जा सकता। सवाल है कि इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि साल 2014 से पहले महाराष्ट्र में भाजपा चौथे और हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी थी। मोदी लहर और महाराष्ट्र की 15 साल, हरियाणा की 10 साल और केंद्र सरकार की 10 साल के जबरदस्त सत्ता विरोधी रुझान के बूते दोनों राज्यों में वह पहले नंबर की पार्टी बन पाई। इस चुनाव में पांच साल का सत्ता विरोधी रुझान भाजपा के खिलाफ था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती नंबर एक की स्थिति बरकरार रखने और सत्ता में वापसी की थी। पार्टी ने दोनों लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरी ओर पांच साल के सत्ता विरोधी रुझान के बाद भी विपक्ष उसे पहले नंबर से हटा नहीं पाया। यही नहीं हरियाणा में भाजपा के वोट में तीन फीसद की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में जरूर दो फीसद वोट की कमी आई, लेकिन पार्टी इस बार सौ सीटें कम पर लड़ी थी। यदि यह विपक्ष की जीत और मोदी-शाह की हार है तो ऐसा सोचने वालों की समझ की बलिहारी। ये ऐसे लोग हैं जो अपनों की गर्दन कटने का शोक मनाने के बजाय विरोधी की अंगुली कटने का जश्न मनाने में यकीन करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि इन पांच वर्षों में दोनों राज्यों में तीन बड़े आंदोलन हुए। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों को मोदी की हार और विपक्ष की जीत के रूप में पेश किया जाना राजनीतिक विश्लेषण का नया तरीका है। इसका सिलसिला गुजरात विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ था। जब स्पष्ट बहुमत से जीतने वाली भाजपा को इसलिए पराजित घोषित कर दिया गया कि उसकी सीटें कुछ कम हो गईं और पिछले करीब तीन दशक से सत्ता तक न पहुंच पाने वाली कांग्रेस को विजेता के रूप में पेश किया गया।

जनसंघ से भाजपा के राजनीतिक सफर में पार्टी जिस भी राज्य में पहली बार सत्ता में आई वह अगले चुनाव में वापसी नहीं कर सकी। वह चाहे 1977 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हो या फिर 1991 में उत्तर प्रदेश या 2008 में कर्नाटक हो। गुजरात इस मामले में अब तक एकमात्र अपवाद था। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए नहीं कि ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं भाजपा संगठन की दृष्टि से भी इन राज्यों की महाराष्ट्र और हरियाणा से तुलना नहीं की जा सकती। तो क्या इन दोनों राज्यों में भाजपा में कोई समस्या नहीं है। ऐसा कहना सच्चाई से भागना होगा। दरअसल समस्या पुरानी है, लेकिन वह मोदी-शाह के युग में भी कम नहीं हो रही है। भाजपा का एक विशेष गुण है। सत्ता में आते ही उसकी सरकार के मंत्री पहले अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करते हैं, फिर आम जनता को। इसके बाद चुनाव आते-आते दोनों मिलकर पार्टी को हराते हैं। मोदी-शाह के युग में फर्क इतना हुआ है कि यह नुकसान अब मंत्रियों तक सीमित हो गया है। दोनों राज्यों में हारने वाले मंत्रियों की संख्या और पार्टी की कम हुई सीटों की संख्या गिन लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। मतलब यह कि जितने मंत्री, लगभग उतनी सीटें हारना तो तय है। यह नतीजा है उस सोच का जो मानती है मोदी नाम केवलम यानी हम मंत्री बन गए तो अब जनता ठेंगे पर। मोदी जी तो चुनाव जिताने के लिए हैं ही।

जब यह सोच 15 साल (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) से चल रही हो तो मोदी-शाह के लिए भी कठिन हो जाता है। इसी तरह यदि पांच साल में लुटिया डुबोने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया हों तो मोदी-शाह के लिए रफू करना और कठिन हो जाता है। मतादाता ने ऐसे नेताओं को संदेश दिया है कि भरोसा मोदी-शाह पर है, आप पर नहीं। ऐसे में देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल खट्टर की जीत की अहमियत और बढ़ जाती है। पार्टी के लिए भी संदेश है कि मंत्री काम करने के लिए होते हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं। भाजपा के लिए इन दो राज्यों के जनादेश का यह भी संदेश है कि जब बात मोदी की हो तो मतदाता मुकाबले में खड़े किसी नेता पर भरोसा नहीं करता, पर जब मनोहर लाल खट्टर के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों और देवेंद्र फड़नवीस के सामने शरद पवार हों तो मुकाबला वैसा एकतरफा नहीं रहता। यह मोदी पर भरोसे का ही नतीजा है कि पवार और हुड्डा सारी ताकत लगाकर भी जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। भाजपा के राजनीतिक विस्तार के रास्ते की बाधा केवल सामाजिक संतुलन को साधने और उसे मजबूत बनाने की ही नहीं है। कुछ सहयोगी भी हैं। इसमें शिवसेना का नाम सबसे ऊपर है।

शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो सत्तारूढ़ और विरोधी दल की भूमिका एक साथ चाहती है। वह भीख भी मांगती है और गाली भी देती है। उसे जो मिलता है उससे वह कभी संतुष्ट नहीं होती। चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन से वह परेशान नहीं होती। उसके वोट भाजपा से ज्यादा घटे और उसकी स्ट्राइक रेट भी भाजपा से खराब है। शिवसेना को भाजपा से लगभग आधी सीटें मिली हैं, फिर भी उसे ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए। उसकी समस्या यह है कि लंबे समय तक देने वाली पार्टी से अब वह मांगने वाली पार्टी हो गई है। यह बात उसे हजम नहीं हो रही है।

शिवसेना के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ना भाजपा की रणनीतिक भूल थी जिसका खामियाजा वह भुगत रही है। अब देखना यह है कि भाजपा 2014 की तरह अपने रुख पर कायम रहती है या शिवसेना की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाती है? महाराष्ट्र के बाद अगला मोर्चा बिहार में खुलेगा। भाजपा शिवसेना के आगे झुकी तो उसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सामने भी झुकना पड़ेगा। आखिर जब शिवसेना पांच महीने में ही भूल गई कि लोकसभा में उसे जो सीटें मिलीं वे उद्धव ठाकरे के नहीं मोदी के नाम पर मिली हैं तो जनता दल यूनाइटेड क्यों याद रखेगा?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

# भारत को एक करने वाले सरदार



केसी त्यागी

**यदि दृढ़ निश्चयी सरदार पटेल न होते तो शायद आज भारत का भौगोलिक नक्शा भिन्न होता**



सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती इसलिए विशेष है, क्योंकि उनके स्मरण में 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर को आधिकारिक रूप से दो भागों में विभाजित करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसके पहले गृह मंत्रालय की ओर से यह घोषणा की गई थी कि पुलिस एवं सभी अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालयों में उनका चित्र अवश्य इस्तेमाल किया जाए। इससे यही स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार के लिए महात्मा गांधी के बाद लौह पुरुष सरदार पटेल सर्वाधिक सम्मानित शख्सियत हैं। कांग्रेस सरकार ने तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने में लगभग 40 वर्ष लगा दिए थे। यह सर्वविदित है कि कैसे सरदार पटेल अपनी अनुशासनात्मक क्षमता और मजबूत नेतृत्व के बल पर 565 प्रांतों को भारत के साथ जोड़ने में कामयाब हुए थे। सरदार पटेल के इस योगदान के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 182 मीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया था। यह मूर्ति स्थल आज पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। यह सच है कि सरदार पटेल न होते तो आज भारत का भौगोलिक नक्शा शायद भिन्न होता। जूनागढ़, जोधपुर और खासतौर पर हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने में उनकी साम, दाम, दंड एवं भेद की नीतियां आज भी उन्हें इतिहास के पन्नों पर सजीव और प्रासंगिक बनाए हुए हैं।

जब पाकिस्तान का बनना तय हो गया था तब देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां थीं। 1946 के कैबिनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के अनुसार बंगाल, पंजाब और असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे थे। तब दूरदर्शी सरदार पटेल द्वारा इस योजना का कड़े शब्दों में विरोध किया गया। उन्होंने कहा, 'यह प्रस्ताव तो पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव से भी ज्यादा खराब है।' बाद में सरदार पटेल ने पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया और पूरा का पूरा असम भारत का हिस्सा बना लिया गया। यह ध्यान रहे कि तब असम एक तरह से पूरा पूर्वोत्तर था। देश के एकीकरण के अपने प्रयासों के दौरान सरदार पटेल ने समय की मांग को बखूबी समझने और उसके अनुरूप चलने का काम किया। हैदराबाद और जूनागढ़ के नबाव के खिलाफ उन्होंने बल और विवेक, दोनों का इस्तेमाल किया।

सरदार पटेल दबे-कुचले, मजदूरों, गरीबों एवं किसानों की भी मजबूत आवाज थे। आजादी के आंदोलनों में मुख्य भूमिका निभाने के साथ ही वे उन सभी सामाजिक वर्गों का भी नेतृत्व कर रहे थे जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शोषित हो रहे थे। जनवरी 1928 में में अंग्रेजी हुकूमत ने एक तालुका के समूचे किसानों का भूमि कर लगभग 22 प्रतिशत बढ़ा दिया, जो लगभग दोगुने के करीब था। उसी तालुका के अंतर्गत बारदोली भी आता था। जहां के आश्रमों के संघ अध्यक्ष के पद पर पटेल आसीन थे। इस मुद्दे को पटेल ने चुनौती के रूप में लिया। किसानों को एकजुट कर उन्होंने बारदोली आंदोलन किया। पटेल ने किसानों से अंग्रेजों के आदेश के खिलाफ जाकर भू-कर नहीं देने का आह्वान किया। उन्हें बारदोली की महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के साथ खेड़ा किसान आंदोलन का अनुभव भी सरदार पटेल के इस आंदोलन के मार्गदर्शन में सहायक रहा। उनके सफल नेतृत्व और किसानों की एकता के फलस्वरूप अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। भू-कर में संशोधन किया गया, किसानों को रियायत दी गई, जबरन हड़पी गई जमीनें तथा पालतू जानवर वापस किए गए। इससे किसानों में विश्वास, संतोष और साहस का संचार हुआ। अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के अलावा उन्होंने समाज को सशक्त करने का काम भी किया। उनके अनुयायियों ने गांव के सभी समुदायों के लोगों को चरखा चलाना तथा सूत कातना सिखाया। किसानों के बीच पटेल की सकारात्मक पैठ को देखते हुए स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि से नवाजा। यह पटेल की पहली सफलता नहीं थी। खेड़ा के प्रसिद्ध किसान आंदोलन में भी महात्मा गांधी के साथ उनकी भूमिका अहम रही थी। उस आंदोलन की भी शुरुआत भूमि कर के लिए ही हुई थी। 1918 में गुजरात का यह क्षेत्र भीषण अकाल की मार झेल रहा था। किसान भूमि कर देने में लाचार एवं असहाय हो चुके थे। किसानों की समस्याओं की अनदेखी करते हुए अंग्रेजों ने कर में बढ़ोतरी कर दी थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन का मोर्चा संभाला जिसमें सरदार पटेल उनके मुख्य सिपहसालार की भूमिका में थे। आंदोलन इतना सशक्त हो चुका था कि अंततः ब्रिटिश शासन को द्विपक्षीय समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके तहत कर माफी पर विचार, बढ़ाए गए कर में कटौती और जबरन हड़पी गई जमीनें एवं वस्तुओं की वापसी पर सहमति बनी।

सरदार पटेल के निर्णय दूरगामी एवं अनुशासित प्रवृत्ति के होते थे। उन पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव था। धर्मनिरपेक्षता उन्हें गांधी जी से दीक्षा में प्राप्त हुई थी। गांधी जी के कारण ही उन्होंने खादी के प्रति अपनी आस्था जागृत की थी। गांधी जी के संपर्क में आने से पहले वह पश्चिमी वेशभूषा से प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के कदमों पर चलकर 'विदेशी सामग्री जलाओ' नामक कई विरोध प्रदर्शनों को भी अंजाम देने का कार्य किया। दांडी मार्च के दौरान स्वयं महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि खेड़ा सत्याग्रह में मुझे सरदार पटेल की वजह से ही सफलता मिली और आज इन्हीं की वजह से मैं यहां दांडी में भी हूं। सरदार पटेल जिन्हें गांधी जी अपनी सफलता का कारण मानते थे, आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे वह किसानों का सवाल हो या फिर जवानों का। धर्मनिरपेक्षता उनकी दूसरी मजबूत कड़ी थी। इसके जरिये ही वे मजबूत और अखंड भारत का सपना देखते थे। आज यह कहीं आवश्यक है कि हम सरदार पटेल के आदर्शों और मार्गों का अनुसरण कर उनके सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। यही उनकी जयंती पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### संतोष धर्म

चाणक्य कहते हैं, 'शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई धर्म नहीं।' सुख के लिए विश्व में सभी जगह चाहत है, पर सुख उसी को मिलता है, जिसे संतोष करना आता है। एक जिज्ञासा उठती है कि संतोष है क्या? संतोष का अभिप्राय है, इच्छाओं का त्याग। सभी इच्छाओं का त्याग करके अपनी स्थिति पर संतोष करना ही सुख को प्राप्त कर लेना है। जीवन के साथ इच्छाएं, कामनाएं एवं आकांक्षाएं रहती ही हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि सुखी जीवन के लिए हमारी इच्छा शक्ति पर कहीं तो विराम होना चाहिए। इच्छा के वेग में विराम को ही संतोष की संज्ञा दे सकते हैं। आचार्य गोरेलाल जी का मत है, 'संतोष मन की वह अवस्था है, जिसमें मनुष्य पूर्ण तृप्ति या प्रसन्नता का अनुभव करता है, अर्थात इच्छा रह ही नहीं पाती।' जीवन की गति के साथ संपत्ति और समृद्धि की दौड़ से वह सुख नहीं मिलता, जो संतोष रूपी वृक्ष की शीतल छांव में अनायास मिल जाता है। हमें चाहिए कि हम प्रयत्न और परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रसन्नता पर संतोष करना सीखें। निष्काम कर्मयोग, इच्छाओं का दमन, लोभ का त्याग अथवा इंद्रियों पर अधिकार-ये सभी उपदेश संतोष की ओर ले जाने वाले सोपान ही तो हैं।

सच है, संतोष प्राकृतिक संपदा है, ऐश्वर्य कृत्रिम गरीबी। संतोष का आदर्श यही है कि हम इच्छाओं को सीमित रखकर सत्य एवं ईमानदारी से भरा श्रम करें और फल की चिंता न करते हुए उसे परमात्मा और परिस्थितियों पर छोड़ दें। हमें इस तथ्य का भली प्रकार बोध होना चाहिए कि सुखी होने का भाव है-दूसरों को सुखी बनाना। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध व्यक्तित्व ही सच्चे सुख की रसधार में सदैव स्नान करता है। आत्मा में सुख-सौंदर्य की विपुल वर्षा के लिए संतोष एक सजीला मेघ है। सुख और संतोष प्रायः साथ चलते हैं। संतोष मेघ है और सुख उससे बरसने वाला जल। संतोष सुख का सबसे बड़ा साधन है, जो मस्तिष्क के झुकाव पर निर्भर करता है। यदि मन से सुख मान लिया तो विपुल व्याधियां भी क्षण भर में उड़ जाती हैं।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

# महिला सुरक्षा के चिंतनीय हालात

मीनाक्षी भटनागर

> दुख की बात है कि कानूनी सख्ती भी आधी आबादी के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है

हाल ही में आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़े महिलाओं की सुरक्षा की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में आधी आबादी के खिलाफ अपराध में करीब छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 359849 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में 338954 मामले दर्ज किए गए थे। घर के भीतर अपनों का दुर्व्यवहार हो या नाबालिग बच्चियों के शोषण के मामले, हर उम्र, हर वर्ग की महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 56011 मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा पूरे देश में हुए अपराधों का 15.6 फीसद है। महिलाओं के खिलाफ सबसे असुरक्षित पांच राज्यों की फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पायदान पर बंगाल, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और पांचवें पायदान पर राजस्थान है। अफसोस कि देश के बड़े राज्यों में महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हालात चिंतनीय हैं। वहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित पांच राज्यों में लक्षद्वीप, दादर-नगर हवेली, दमन-दीव, नगालैंड और पुदुचेरी जैसे छोटे प्रांत हैं।

एनसीआरबी के आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश में बहुत सी महिलाएं अपने पति या रिश्तेदारों की क्रूरता का भी शिकार बन रही हैं। अपनों की बर्बरता के बंगाल से 16800, उत्तर प्रदेश से 12653, राजस्थान से 11508, असम से 9782 और तेलंगाना से 7838 मामले सामने आए हैं। ये पांच राज्य महिलाओं को घर में मिलने वाली अपनों की प्रताड़ना में सबसे आगे हैं। गौरतलब है कि एनसीआरबी वही आंकड़े सामने रखता है, जो पुलिस से मिलते हैं। जाहिर है महिला अपराधों से जुड़े वास्तविक आंकड़े इनसे कहीं ज्यादा ही होंगे। चिंतनीय है कि कानूनी सख्ती भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए आरोपी को फांसी की सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। कई राज्यों ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर नियम भी बनाए हैं। बावजूद इसके समाज में महिलाओं के प्रति आपराधिक प्रवृत्ति रखने वालों के बढ़ते दुस्साहस और नकारात्मक सोच की बदौलत सामने आए ये आंकड़े भयभीत करने वाले हैं।

देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में समाज की संरचना काफी हद तक बदल गई है। बेटियां अब पढ़-लिख कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। कामकाजी स्त्रियां दोहरी जिम्मेदारी उठा रही हैं। वे विज्ञान की दुनिया से लेकर घर की देहरी तक अपनी भूमिका का निर्वहन पूरे मनोयोग से कर रही हैं। साथ ही वे समाज और परिवार में संस्कार, सरोकार और जिम्मेदारी के भाव की बुनियाद भी पुख्ता कर रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनके जीवन से भी असुरक्षा का अंधकार मिटे। अपनी पहचान बनाने और सपने पूरे करने की राह पर भय नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का भाव उनके हिस्से आए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### सही कूटनीति

कूटनीति को नई धार देता भारत शीर्षक से लिखे अपने आलेख में ब्रिगेडियर आरपी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के नए खेवनहार बने तुर्की और मलेशिया की भौगोलिक-कूटनीतिक स्थिति की सटीक समीक्षा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, जो लंबे समय से वहां की सत्ता पर काबिज हैं, ने एक मुहिम चलाकर वहां के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट करने का काम किया है। उन्होंने तुर्की में कुर्दिश राष्ट्रीयता की पहचान के लिए लड़ रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को कठोरता से दबाने की कोशिश की है। इसके अलावा अब सीरिया से लगी सीमा पर कुर्दों के खिलाफ हमला बोल दिया है। यह तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। भारत ने उचित ही तुर्की की इस एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया है। उसके पास यह विकल्प है कि जरूरत पड़ने पर वह इन कुर्दों को रणनीतिक-कूटनीतिक सहायता देने पर विचार कर सकता है। भारत ने पहले ही ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों, जिनके तुर्की के साथ गंभीर सीमा विवाद हैं, की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही है। बात करें मलेशिया की तो उसे साधने के लिए भारत सरकार ने वहां से पाम ऑयल के आयात को बंद करने के संकेत दिए हैं। इससे उसकी अकड़ कम होती है तो ठीक वर्ना भारत को चाहिए कि वह दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में सिंगापुर और इंडोनेशिया से उसके सीमाई विवादों में उन देशों का साथ दे। मलेशिया ने पूर्व में हुए जोहोर समझौते का उल्लंघन कर किया है, जिससे सिंगापुर काफी चिंतित है। इसके अलावा पेड्रा ब्रांका क्षेत्र पर सिंगापुर दावा कर रहा है और जो इस समय मलेशिया के नियंत्रण में है। भारत अपनी तरकश में रखे इस तीर का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बार ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्सटन ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में केवल हमारे हित स्थाई होते हैं, दोस्त या दुश्मन नहीं। निःसंदेह मोदी सरकार ने राष्ट्र हित में इस सोच पर आगे बढ़ने का हौसला दिखाया है।

चंदन कुमार, देवघर

### आस्था का महापर्व

छठ कभी पूर्वांचल क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे देश के विभिन्न भागों के साथ ही विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसका कारण बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का रोजगार की तलाश में बाहर निकलना है। वे जहां भी गए वहीं पर इसे शुरू कर दिया और दूसरे लोगों ने भी इसकी महत्ता को समझा। इसी वजह से बहुत से दूसरे इलाके के लोग भी इस पूजा में भाग लेने लगे हैं। यह महापर्व भाईचारा एवं एकता को दर्शाता है। कई जगह मुस्लिम महिलाएं भी छठ व्रत करती हैं। दुनिया में सबसे पवित्र पर्व में छठ पर्व के गिनती होती है, इसके साथ ही यह दुनिया का पहला ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते एवं उगते दोनों अवस्थाओं में सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व स्वच्छता एवं पर्यावरण का संदेश देता है। इस महापर्व में सफाई का ध्यान एवं प्रकृति से जुड़ी हुई ज्यादातर वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है।

जय किशोर तिवारी, शिक्षक, नई दिल्ली

### युवाओं को मिले रोजगार

आज भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। उससे लगता है कि भारत जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ रहा है। देश में मेडिकल व इंजीनियरिंग के तमाम कॉलेज हैं और वहां से हर साल बड़ी मात्रा में बच्चे पढ़कर निकलते हैं, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। इनमें से कुछ बच्चे रोजगार के अभाव में अपराध का रास्ता अपना लेते हैं, जिससे एक शिक्षित व्यक्ति अपराधी बन जाता है। सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे, जिससे हर शिक्षित को रोजगार मिल सके।

मो. जमील, नई दिल्ली

### सोच बदलने की जरूरत

हमें स्वस्थ बेटा तो चाहिए पर जो बेटी उस पुत्र को जन्म देगी उसके स्वास्थ्य, लालन-पालन व शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता बरती जाती है। हमें यह क्यों समझ नहीं आता कि अस्वस्थ बेटियां क्या स्वस्थ बेटा पैदा कर सकती हैं? कभी नहीं। हमें बेटियों के प्रति अपनी इस पुरानी घटिया सोच को तुरंत तिलांजलि देकर उनके जन्म और उनके लालन पालन को एक उत्सव के रूप में अपनाना होगा तभी हमारी अगली पीढ़ियां बलशाली होंगी।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें :**
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।